जबलपुर | बुधवार | 22 जुलाई 2026 | वर्ष 77 | अंक 179 | पृष्ठ 20 | मूल्य रु. 6.00
navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत
राष्ट्रीयता के प्रहरी 1934 से

राहुल को उठा ले गई पुलिस

पीएम मार्ग पर प्रतिपक्ष नेता राहुल, प्रियंका, खड़गे दे रहे थे धरना

प्रवेश कुमार मिश्र

नई दिल्ली, 21 जुलाई. सड़क से शुरू हुआ छात्र आंदोलन कराहते घायलों के साथ अस्पताल की दीवारों से उपजी आक्रोश की चिंगारी के साथ देखते ही देखते नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ देश के सबसे सुरक्षित और रसूखदार राजनीतिक गलियारे तक फैल गया है. इतना ही नहीं इस घमासान का सीधा असर संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी दिखाई दिया जहां विपक्षी हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई.

पिछले दिनों पुलिसिया कार्रवाई में घायल लगभग 6 छात्रों में से अभी भी अस्पताल में भर्ती कुछ छात्रों को देखने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा कर घायल छात्रों और एक छात्रा जो वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है उनके व्यथित परिजनों से मुलाकात की. कांग्रेस ने इसे एक सामान्य प्रशासनिक विफलता मानने से साफ इनकार करते हुए इसे देश की युवा शक्ति के सुनहरे भविष्य पर एक सोची-समझी चोट करार दिया है. हालांकि सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना.

अस्पताल से निकलते ही आंदोलन की आंच सड़कों से होते हुए देश के सबसे सुरक्षित राजनीतिक गलियारे तक पहुंच गई. राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास की तरफ मार्च किया और वहां धरने पर बैठ गए. हाथों को नायलॉन की रस्सियों से बांधकर किया गया .यह अनूठा प्रदर्शन प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश दे रहा था कि सरकार युवाओं की आवाज को बांधने का प्रयास कर रही है. कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार के सामने 5 प्रमुख मांगें रखी है. जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, पेपर लीक मामलों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच, घायल छात्रों को मुआवजा और पुलिस कार्रवाई पर तत्काल रोक शामिल है.

> विपक्ष की मांग अब सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं है बल्कि वे सीधे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से इस पुलिसिया कार्रवाई की जिम्मेदारी लेते हुए उनके इस्तीफे और राष्ट्र से माफी की मांग पर अड़ गए हैं. हालांकि इस अभूतपूर्व गतिरोध के बीच, केंद्र सरकार की ओर से केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे. उन्होंने धरना दे रहे राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं से बातचीत की और स्थिति को संभालने का प्रयास किया.

सरकार नीट पर संसद में चर्चा के लिए तैयार : जितेन्द्र सिंह

नई दिल्ली 21 जुलाई. सरकार ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री आवास के निकट धरने पर बैठे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से बातचीत के बाद नीट और उससे संबंधित आंदोलन के सभी विषयों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है लेकिन श्री गांधी दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अपनी बात से मुकर गये हैं तथा उन्होंने अब धरना समाप्त करने के लिए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी जोड़ दी है.

श्री गांधी मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा कुछ अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े और वहीं आवास के करीब अचानक धरने पर बैठ गये। यह देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह उनसे मिलने गये और श्री गांधी से बातचीत की। उनके साथ केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी थे।

मध्यप्रदेश में यूसीसी विधेयक पारित

सदन में यूसीसी विधेयक को लेकर जमकर हंगामा

अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बनेगा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 जुलाई. मप्र विधानसभा में मंगलवार का दिन नया इतिहास लिख गया, जब घड़ी में ठीक 3 बजकर 9 मिनट और 27 सेकंड हुए थे, तब विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने मप्र समान नागरिक संहिता 2026 के पारित होने की घोषणा की. इसी के साथ मप्र अब देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है, जहां यूसीसी लागू होगा.

सदन में पारित होने के बाद विधेयक को राज्यपाल को भेजा जाएगा. राज्यपाल की हरी झंडी मिलते ही विधेयक कानून बन जाएगा. इस संबंध में अधिसूचना भी जारी होगी. प्रदेश के नागरिकों को अब देश की आजादी के सबसे बड़े त्यौहार यानी 15 अगस्त से पहले समान नागरिक संहिता की सौगात मिल सकती है. अब धर्म के आधार पर किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा. सभी के लिए एक समान कानून लागू होंगे.

यूसीसी विधेयक के पारित होने से पहले सदन में जमकर हंगामा हुआ. यूसीसी विधेयक पर जैसे ही चर्चा की शुरुआत हुई, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने विरोध करते हुए आसंदी के सामने प्रदर्शन किया. वे पूरे समय नारेबाजी करते रहे. वे विधेयक को सदन में पारित कराने से पहले प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग कर रहे थे. विपक्ष के हंगामें के कारण सदन की कार्यवाही को दो बार स्थगित भी करना पड़ा. पहले सदन की कार्यवाही को 1 मिनट और फिर बाद में 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया. इस दौरान अध्यक्ष तोमर विपक्षी सदस्यों को अपनी सीट पर जाने का अनुरोध करते रहे, लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ. हंगामें के बीच ही अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए विधेयक में चर्चा के लिए शामिल विधायकों के नाम पुकारना शुरू किया, लेकिन विपक्ष के सदस्यों में चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, केवल आरिफ मसूद और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ही इस मामले में विपक्ष का पक्ष रखा.

चर्चा की शुरुआत में ही कांग्रेस सदस्य आरिफ मसूद ने विधेयक को लेकर संशोधन प्रस्ताव दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी जल्दी क्यों? जैसे जनजाति को छूट दी गई है, वैसे ही मुस्लिमों को भी छूट दिया जाना चाहिए. विधेयक संविधान के आर्टिकल 29 का उल्लंघन है. उन्होंने इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की. वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विधेयक पर चर्चा से पहले दो दिन पहले सदस्यों को सूचना देना होता है, लेकिन नहीं दिया गया.

अलग-अलग मजहबी तोल-कांटा नहीं होगा : सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधेयक पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है, युग परिवर्तन की बेला है. जब विधाता की द्रष्टि में सब एक हैं, तो फिर इंसान भेदभाव क्यों करे? कांग्रेस ने वोटों की राजनीति के लिए हमेशा पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया है. मप्र एक विधान से चले, इसलिए ये कानून लागू किया जा रहा है. आज के बाद भेदभाव से मुक्ति मिलेगी. गोवा, असम, उत्तराखंड के बाद मप्र यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बनेगा. सीएम ने कहा कि अब अलग- अलग मजहबी तोल-कांटा नहीं होगा, सब एक साथ तोले जाएंगे. विपक्ष के खाने के दांत अलग है और दिखाने के अलग है. विरोध करने पर इनके घर की माताएं- बहनें इन्हें माफ नहीं करेंगी. विपक्ष के हालात थाली के बैंगन की तरह है.

पंजाब में आतंकी साजिश नाकाम, 17 गिरफ्तार

मोगा (पंजाब) 21 जुलाई. पंजाब पुलिस ने मोगा में एक कथित आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, विस्फोटक सामग्री, एक इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और एक मैगजीन बरामद की गई है.

- **आईईडी और हथियार बरामद**
- **ट्रेन को निशाना बनाने की साजिश विफल**

मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच जारी है. पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में इकबाल सिंह उर्फ रवि ढालीवाल को इस कथित साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया है. पुलिस के अनुसार, वह वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम (यूके) में रह रहा है और कथित रूप से आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है. डीजीपी के मुताबिक, आरोप है कि उसके निर्देश पर आरोपियों ने मोगा के थाना सदर पर ग्रेनेड हमला किया था. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि समूह फिरोजपुर से जम्मू जाने वाली ट्रेन में आईडी लगाने की साजिश रच रहा था.

> पुलिस का कहना है कि समय रहते कार्रवाई कर इस योजना को विफल कर दिया गया. मामले में भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत थाना सदर मोगा में एफआईआर दर्ज की गई है।पंजाब पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला जा रहा है. जांच एजेंसियां इस कथित साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उनके संभावित संबंधों की भी पड़ताल कर रही हैं.